शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 50 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 50 अंक – 20 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 12 – 19 मई 2025 मूल्य पांच रूपये

क्या स्व. वीरभद्र सिंह की प्रतिमा की स्थापना रिज पर हो पायेगी?

सुमन कदम के पत्र से उठी आशंकाएं

शिमला/शैल। क्या स्व. वीरभद्र सिंह की प्रतिमा शिमला के रिज पर स्थापित हो पायेगी? यह सवाल इसलिये उठ खड़ा हुआ है क्योंकि प्रस्तावित स्थापना को लेकर एक सुमन कदम ने नगर निगम शिमला को भेजे एक पत्र पर आपत्ति उठाई है। कुसम्पटी की कथित निवासी सुमन कदम ने महापौर के नाम भेजे पत्र में कदम ने सर्वोच्च न्यायालय के 2013 में यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम स्टेट ऑफ गुजरात मामले में आये फैसले के आधार पर एतराज उठाये हैं। सुमन कदम के पत्र में कोई तारीख दर्ज नहीं है। सुमन कदम ने जुब्बल – कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा है। कुछ लोगों के मुताबिक सुमन कदम काफी अरसा पहले अपने मकान मालिक के साथ हुये झगड़े के बाद शायद कसुम्पटी छोड़कर जा चुकी है। लेकिन उनके ऐतराज में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का जिक्र है इसलिये यह एतराज अपने में गंभीर हो जाता है। नगर निगम ने इस एतराज को सचिवालय में सरकार के पास भेज दिया है। विधि विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का अनुमोदन करते हुये इस पर मन्त्री परिषद को निर्णय लेने की राय दी है। प्रशासनिक और राजनीतिक हल्कों में इस एतराज को राजनितिक आईने से देखा जा रहा है।

स्व. वीरभद्र छः बार प्रदेश के मुख्यमन्त्री रहे हैं इस नाते उनके प्रशंसकों और समर्थकों की लम्बी लाईन है। उनके परिजन और समर्थक चाहते है कि उनके प्रदेश की राजनीति में विशेष योगदान के लिये उनकी प्रतिमा रिज पर स्व. डॉ. वाई. एस. परमार की बगल में स्थापित करके उन्हें सम्मान दिया जाये। इसलिये उनके समर्थकों और परिजनों ने इसके लिये राजा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन का गठन करके यह ऐलान किया है कि इस मूर्ति स्थापना पर होने वाला सारा खर्च फाउंडेशन उठायेगी और सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं ली जायेगी। लेकिन फाउंडेशन के इस ऐलान के बाद मुख्यमंत्री ने प्रतिभा सिंह को पत्र भेज कर यह कहा है कि इस प्रतिमा स्थापना पर होने वाला सारा खर्च और उसके भविष्य में रख – रखाव पर आने वाला सारा खर्च सरकार उठायेगी। नगर निगम ने इस विषय पर निगम हाउस में आये एक प्रस्ताव के उत्तर में इस प्रतिमा स्थापना के लिये रिज पर जगह देने की भी फैसला कर लिया है। निगम में प्रस्ताव 2024 में आया था निश्चित है कि जब निगम में इस बारे में प्रस्ताव आया था उस समय यह ऐतराज़ का पत्र निगम के पास नहीं आया था। क्योंकि अगर यह पत्र आया होता तो इस पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की पृष्ठभूमि में विचार करके फैसला लिया जाता।

स्व. वीरभद्र सिंह की मृत्यु जुलाई 2021 में हुई थी और उसके बाद ही उनकी प्रतिमा स्थापित किये जाने की मांग आ गयी थी। भाजपा शासन में ही निगम में इस आशय की मांग आ गयी थी। भाजपा ने भी उनकी प्रतिमा स्थापित किये जाने का अनुमोदन किया था। लेकिन विधानसभा चुनाव के कारण यह हो नहीं सका और उसके बाद सरकार बदल गयी। नयी सरकार ने इस बारे कोई हामी नहीं भरी और 2023 में उनकी प्रतिमा शिमला से सौ किलोमीटर दूर सैंज में स्थापित की गयी। स्थापना पर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री शामिल रहे थे। उस समय स्थापना के लिये रिज पर जगह नहीं दी गयी। रिज पर जगह न मिलने पर विक्रमादित्य सिंह ने भावुक रोष भी व्यक्त किया था। 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत का श्रेय भी वीरभद्र सिंह की मृत्यु पर उपजी सहानुभूति लहर को दिया गया था। लेकिन स्थापना के लिये रिज पर जगह न मिल पाने को वीरभद्र सिंह और सुक्खू के राजनीतिक रिश्तों की पृष्ठभूमि में देखा गया। क्योंकि दोनों के राजनीतिक रिश्ते सुखद नहीं रहे हैं। बल्कि उन रिश्तों का की छाया सरकार बनने के बाद भी लगातार देखी जा रही है। आज भी वीरभद्र के समर्थकों की लाइन शायद सुक्खू के प्रशंसकों से लंबी है। बल्कि कांग्रेस अध्यक्षा प्रतिभा सिंह और मुख्यमंत्री सुक्खू के राजनीतिक रिश्ते अभी भी उस पुरानी छाया से बाहर नहीं आ पाये हैं। यह इससे स्पष्ट हो जाता है कि छः माह पहले भंग हुई कार्यकारिणी का अब तक गठन नहीं हो पाया है। अब जिस तरह से सुमन कदम की मूर्ति स्थापना को लेकर एतराज आया है उसे भी राजनीतिक चश्मे से ही देखा जा रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस एतराज को मंत्रिपरिषद के सामने रखा जाता है या नहीं। मंत्रिपरिषद में कौन इस ऐतराज़ का समर्थन करता है या विरोध। लेकिन यह तय है कि स्व. वीरभद्र सिंह की प्रतिमा की स्थापना या उसका इन्कार कांग्रेस को बहुत दूर तक प्रभावित करेगा।

यह है सुमन कदम का पत्र

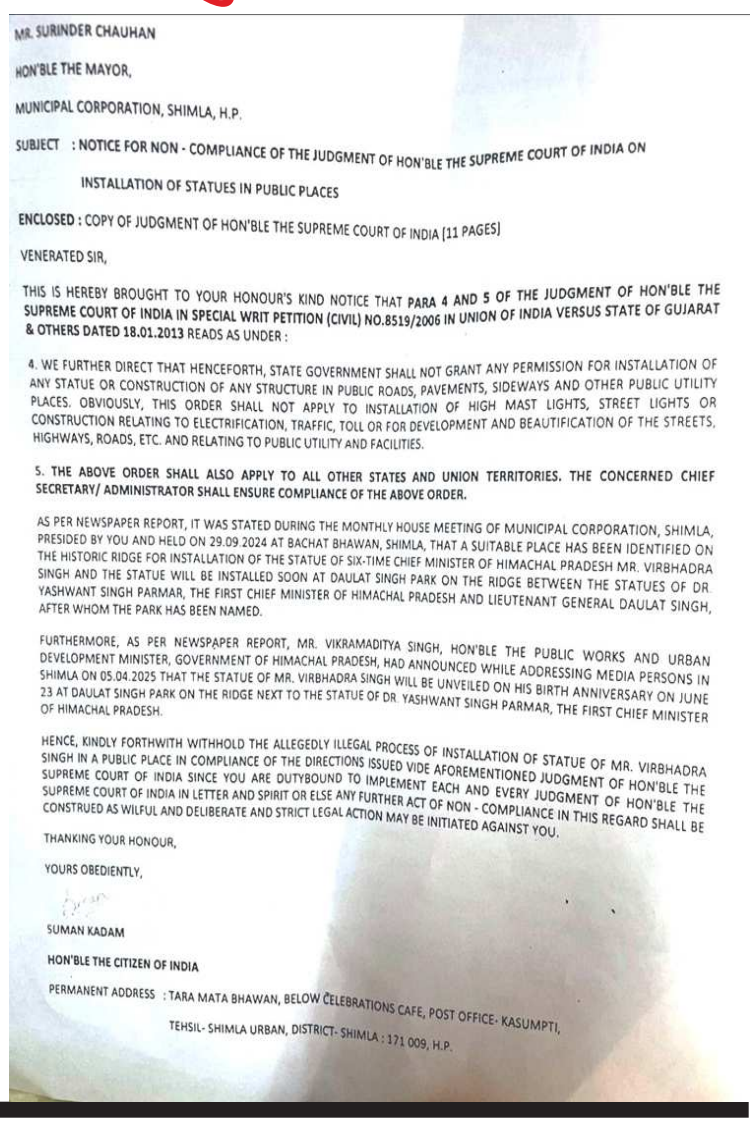

MR. SURINDER CHAUHAN
HON'BLE THE MAYOR,
MUNICIPAL CORPORATION, SHIMLA, H.P.

SUBJECT : NOTICE FOR NON - COMPLIANCE OF THE JUDGMENT OF HON'BLE THE SUPREME COURT OF INDIA ON INSTALLATION OF STATUES IN PUBLIC PLACES

ENCLOSED : COPY OF JUDGMENT OF HON'BLE THE SUPREME COURT OF INDIA (11 PAGES)

VENERATED SIR,

THIS IS HEREBY BROUGHT TO YOUR HONOUR'S KIND NOTICE THAT **PARA 4 AND 5 OF THE JUDGMENT OF HON'BLE THE SUPREME COURT OF INDIA IN SPECIAL WRIT PETITION (CIVIL) NO.8519/2006 IN UNION OF INDIA VERSUS STATE OF GUJARAT & OTHERS DATED 18.01.2013** READS AS UNDER :

4. WE FURTHER DIRECT THAT HENCEFORTH, STATE GOVERNMENT SHALL NOT GRANT ANY PERMISSION FOR INSTALLATION OF ANY STATUE OR CONSTRUCTION OF ANY STRUCTURE IN PUBLIC ROADS, PAVEMENTS, SIDEWAYS AND OTHER PUBLIC UTILITY PLACES. OBVIOUSLY, THIS ORDER SHALL NOT APPLY TO INSTALLATION OF HIGH MAST LIGHTS, STREET LIGHTS OR CONSTRUCTION RELATING TO ELECTRIFICATION, TRAFFIC, TOLL OR FOR DEVELOPMENT AND BEAUTIFICATION OF THE STREETS, HIGHWAYS, ROADS, ETC. AND RELATING TO PUBLIC UTILITY AND FACILITIES.

5. **THE ABOVE ORDER SHALL ALSO APPLY TO ALL OTHER STATES AND UNION TERRITORIES. THE CONCERNED CHIEF SECRETARY/ ADMINISTRATOR SHALL ENSURE COMPLIANCE OF THE ABOVE ORDER.**

AS PER NEWSPAPER REPORT, IT WAS STATED DURING THE MONTHLY HOUSE MEETING OF MUNICIPAL CORPORATION, SHIMLA, PRESIDED BY YOU AND HELD ON 29.09.2024 AT BACHAT BHAWAN, SHIMLA, THAT A SUITABLE PLACE HAS BEEN IDENTIFIED ON THE HISTORIC RIDGE FOR INSTALLATION OF THE STATUE OF SIX-TIME CHIEF MINISTER OF HIMACHAL PRADESH MR. VIRBHADRA SINGH AND THE STATUE WILL BE INSTALLED SOON AT DAULAT SINGH PARK ON THE RIDGE BETWEEN THE STATUES OF DR. YASHWANT SINGH PARMAR, THE FIRST CHIEF MINISTER OF HIMACHAL PRADESH AND LIEUTENANT GENERAL DAULAT SINGH, AFTER WHOM THE PARK HAS BEEN NAMED.

FURTHERMORE, AS PER NEWSPAPER REPORT, MR. VIKRAMADITYA SINGH, HON'BLE THE PUBLIC WORKS AND URBAN DEVELOPMENT MINISTER, GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH, HAD ANNOUNCED WHILE ADDRESSING MEDIA PERSONS IN SHIMLA ON 05.04.2025 THAT THE STATUE OF MR. VIRBHADRA SINGH WILL BE UNVEILED ON HIS BIRTH ANNIVERSARY ON JUNE 23 AT DAULAT SINGH PARK ON THE RIDGE NEXT TO THE STATUE OF DR. YASHWANT SINGH PARMAR, THE FIRST CHIEF MINISTER OF HIMACHAL PRADESH.

HENCE, KINDLY FORTHWITH WITHHOLD THE ALLEGEDLY ILLEGAL PROCESS OF INSTALLATION OF STATUE OF MR. VIRBHADRA SINGH IN A PUBLIC PLACE IN COMPLIANCE OF THE DIRECTIONS ISSUED VIDE AFOREMENTIONED JUDGMENT OF HON'BLE THE SUPREME COURT OF INDIA SINCE YOU ARE DUTYBOUND TO IMPLEMENT EACH AND EVERY JUDGMENT OF HON'BLE THE SUPREME COURT OF INDIA IN LETTER AND SPIRIT OR ELSE ANY FURTHER ACT OF NON - COMPLIANCE IN THIS REGARD SHALL BE CONSTRUED AS WILFUL AND DELIBERATE AND STRICT LEGAL ACTION MAY BE INITIATED AGAINST YOU.

THANKING YOUR HONOUR,

YOURS OBEDIENTLY,

SUMAN KADAM

HON'BLE THE CITIZEN OF INDIA

PERMANENT ADDRESS : TARA MATA BHAWAN, BELOW CELEBRATIONS CAFE, POST OFFICE- KASUMPTI, TEHSIL- SHIMLA URBAN, DISTRICT- SHIMLA : 171 009, H.P.

ऊन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि पर विचार कर रही सरकारः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश वूल फेडरेशन के नवनियुक्त अध्यक्ष मनोज कुमार के नेतृत्व में गद्दी समुदाय के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से भेंट की। उन्होंने इस महत्वपूर्ण पद पर गद्दी समुदाय का प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गद्दी समुदाय की कठिनाइयों से अवगत है तथा इस समुदाय से जुड़े विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऊन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि पर विचार कर रही है तथा सभी हितधारकों से परामर्श के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भेड़-बकरी पालकों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिले, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने संवदेनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए मानसून आपदा 2023 के दौरान प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज प्रस्तुत कर मुआवजे की राशि को कई गुणा बढ़ाया। इस पहल के तहत भेड़, बकरी और सूअर की मृत्यु पर वित्तीय सहायता को 4000 रुपये से बढ़ाकर

6000 रुपये किया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पशुपालक समुदाय की सहायता के लिए इस वित्तीय सहायता को और अधिक बढ़ाया जाएगा।

इससे पहले, हिमाचल प्रदेश वूल फेडरेशन के अध्यक्ष मनोज कुमार ने इस महत्त्वपूर्ण दायित्व के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह समर्पण भाव से कार्य कर मुख्यमंत्री की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उनकी नियुक्ति चंबा और कांगड़ा जिला में रहने वाले पूरे गद्दी समुदाय के लिए गर्व की बात है। उन्होंने भेड़ और बकरियों की मृत्यु पर मुआवजे को बढ़ाने के लिए सरकार की सराहना की। इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और प्रतिनिधिमण्डल के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे।

हिमफेड के नव नियुक्त प्रबंध निदेशक ने उप-मुख्यमंत्री से की शिष्टाचार भेंट

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता संघ लिमिटेड हिमफेड के नव नियुक्त प्रबंध निदेशक जगन ठाकुर ने शिष्टाचार भेंट की।

उप-मुख्यमंत्री ने जगन ठाकुर को नई जिम्मेदारी संभालने पर शुभकामनाएं दीं और आशा व्यक्त की कि उनके कुशल नेतृत्व में हिमफेड राज्य के सहकारी क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुएगा। उन्होंने कहा कि हिमफेड प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इसके सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है और इसमें हिमफेड की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जगन ठाकुर अपने प्रशासनिक अनुभव एवं दक्षता से हिमफेड की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावशाली बनाएंगे।

इस भेंट के दौरान विभिन्न सहकारी योजनाओं एवं उपभोक्ता कल्याण से जुड़ी गतिविधियों पर भी विचार-विमर्श हुआ।

शिक्षा विभाग में कार्यरत 778 अंशकालीन जलवाहकों की सेवाओं को नियमित किया गयाः शिक्षा मंत्री

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में कार्यरत 778 अंशकालिक जलवाहकों को नियमित किया है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च, 2025 तक अंशकालिक जलवाहक और दैनिक वेतनभोगी के रूप में संयुक्त रूप से 11 वर्ष की सेवाएं पूरी कर ली थीं, को चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर इनकी सेवाओं को नियमित किया गया है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा किया है। वर्तमान राज्य सरकार कर्मचारियों की जायज मांगों के प्रति संवदेनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें पूरा कर, लाभान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार ने सत्ता में आने के बाद शिक्षा क्षेत्र में अनके क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार हुआ है। राज्य सरकार विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों को भर रही है और शिक्षकों के 15000 पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें प्राथमिक शिक्षा विभाग में 3900 पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से 3100 पद शीघ्र ही भरे जाएंगे। प्री-प्राइमरी शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए 6200 नर्सरी अध्यापकों की नियुक्ति की जा रही है।

रोहित ठाकुर ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के दौरान शिक्षा क्षेत्र में भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी, लेकिन वर्तमान सरकार रिक्त पदों को भरकर शिक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए प्रमुखता से कार्य कर रही है। प्रदेश भर के शिक्षण संस्थानों में कार्यरत 200 से अधिक कार्यवाहक प्रधानाचार्यो की सेवाएं नियमित की गई हैं। इसके साथ ही उच्च शिक्षा विभाग में 483 सहायक प्रोफैसर की भर्ती की गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने पिछले अढ़ाई वर्षो के दौरान स्कूलों में 700 लैक्चरर की नियुक्ति की है, जबकि पूर्व भाजपा सरकार ने पांच वर्षो के कार्यकाल के दौरान केवल 511 लैक्चरर की नियुद्रि की थी।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किए गए सुधारों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की रैंकिंग में भी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि जनवरी, 2025 में जारी हुई वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के पढ़ने का स्तर देश भर में सर्वश्रेष्ठ है। इस सर्वेक्षण के अधिकांश मापदंडों पर हिमाचल प्रदेश को स्कूली शिक्षा में देशभर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य आंका गया है।

लारजी विद्युत परियोजना पुनः बहाल कर पूर्ण रूप से कार्यशील की गई

शिमला/शैल। कुल्लू जिले में 126 मेगावाट क्षमता की लारजी जल विद्युत परियोजना को पूरी तरह बहाल कर कार्यशील किया गया है। यह परियोजना 9 और 10 जुलाई, 2023 को ब्यास नदी में आई बाढ़ के कारण पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस परियोजना को बहाल करने का कार्य दो वर्ष से भी कम समय में पूर्ण हुआ है। राज्य सरकार के दक्ष और मजबूत प्रयासों के कारण यह कार्य संभव हुआ, जिससे बड़े आर्थिक नुकसान से बचाव हो पाया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में, राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना के पुनः कार्यशील करने के लिए प्रारम्भ में 25 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई। इसके पश्चात 35 करोड़ रुपये और तत्पश्चात 185.87 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई।

मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के इंजीनियरों और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और समर्पण की सराहना की, जिन्होंने इस परियोजना को बहाल करने के लिए पूर्ण समर्पण से कार्य किया। उनके अथक प्रयासों से लारजी पॉवर प्रोजैक्ट के यूनिट-1 को 15 जनवरी, 2024 को फिर से शुरू किया गया और 2 मई, 2024 को पॉवर ग्रिड से जोड़ा गया। यूनिट-2 को 9 अगस्त, 2024 को तथा यूनिट-3 17 जनवरी, 2025 को शुरू की गई। वर्तमान में परियोजना के तीनों टरबाइन कार्यशील हैं और विद्युत उत्पादन आरम्भ कर दिया गया है।

बाढ़ के कारण टरबाइन इकाइयों के अंदर भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया था, जिससे वे कई महीनों तक काम नहीं कर पाए। क्योंकि तकनीकी रूप से मलबा हटाना संभव नहीं था, इसलिए मलबे को कार्य बल द्वारा साफ किया गया। भविष्य में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए परियोजना की सुरक्षा के लिए कई निवारक उपाय किए गए हैं। ढलान स्थिरीकरण कार्य के लिए केबल जाल और रॉक-फॉल बैरियर स्थापित किए गए हैं। सर्ज शाफ्ट गेट के पास कार्य पूरा हो गया है और भूस्खलन और गिरने वाले मलबे के जोखिम को कम करने के लिए पॉवर हाउस के प्रवेश द्वार पर कार्य चल रहा है।

इसके अतिरिक्त, भारी बाढ़ के दौरान पानी के प्रवेश को रोकने के लिए प्रवेश सुरंग पर एक मजबूत गेट लगाया गया है। इस तरह के एक गेट का निर्माण आपातकालीन निकास सुरंग में भी किया जा रहा है, जिसमें सुरक्षित व जलरोधी प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए निर्माण कार्य भी किए जा रहे हैं।

3 अगस्त, 1953 को ब्यास नदी पर स्थित लारजी जल विद्युत परियोजना में बड़ी बाढ़ आई थी। इस बाढ़ में 3838.37 क्यूमेक्स पानी का बहाव था, जबकि वर्ष 2023 में आई बाढ़ में 5600 क्यूमेक्स पानी का बहाव था, जो 1953 की बाढ़ की अपेक्षा काफी अधिक था।

प्राकृतिक उत्पादों की बिक्री के लिए इच्छुक किसानों के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान आरंभ

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्राकृतिक रूप से उगाई गई फसलों के बेचने के इच्छुक किसानों का पंजीकरण करने के लिए एक माह का विशेष अभियान आज से आरम्भ किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कृषि विभाग को इस अभियान को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मिशन मोड पर चलाने के निर्देश दिए हैं ताकि अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित किया जा सके।

प्रवक्ता ने बताया कि यह अभियान इस वर्ष 15 जून तक चलेगा। इसके उपरांत प्रदेश सरकार द्वारा बजट का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग की ओर से शिविर लगाकर किसानों का योजना के तहत पंजीकरण किया जाएगा। विभाग द्वारा खण्ड स्तर के अधिकारियों को किसानों की हर सम्भव सहायता प्रदान करने और अभियान से जुड़ी उनकी शंकाओं का समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक रूप से उगाई गई गेहूं, मक्की, कच्ची हल्दी और जौ के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी देने की पहल की है। राज्य सरकार ने प्राकृतिक रूप से उगाई गई गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये प्रति किलोग्राम और मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम किया है। इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक रूप से उगाई गई कच्ची हल्दी के लिए एमएसपी 90 रुपये प्रति किलोग्राम और चंबा जिला के पांगी ब्लॉक में पैदा होने वाली जौ के लिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम एमएसपी निर्धारित की गई है।

प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री की इस अभिनव पहल का उद्देश्य प्राकृतिक रूप से उगाए गए कृषि उत्पादों को एमएसपी प्रदान कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। प्रदेश में दी जाने वाली एमएसपी देश में सबसे अधिक है। इसके अतिरिक्त, हजारों पशुपालकों को लाभान्वित करने के लिए, राज्य सरकार 51 रुपये प्रति लीटर की दर से गाय का दूध भी खरीद रही है, जबकि भैंस के दूध के लिए 61 रुपये प्रति लीटर एमएसपी निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने और पशुपालकों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए इन प्रगतिशील कदमों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रही है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

कुलदीप कुमार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सचिव से भेंट की

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय

सफाई कर्मचारी आयोग के सचिव राहुल कश्यप से भेंट की। उन्होंने राज्य में सफाई कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित विभिन्न मामलों पर चर्चा की। इस अवसर पर आयोग के सदस्य अधिवक्ता विजय डोगरा और दिग्विजय मल्होत्रा भी उनके साथ मौजूद रहे।

कुलदीप कुमार ने सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न उपायों की जानकारी देते हुए बताया कि उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

राहुल कश्यप ने आयोग से हिमाचल में 'नमस्ते योजना' का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

कृषि क्षेत्र में क्रांति के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता: मुख्यमंत्री

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता पर बल दिया है। कृषि विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग, जाइका और आत्मा परियोजनाओं के सभी अधिकारियों को किसानों तक पहुंच स्थापित कर उन्हें प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए प्रमाणीकरण प्रक्रिया सुलभ बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के पंजीकरण के लिए पंचायतों में शिविर आयोजित करने पर बल दिया।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने एपीएमसी के अध्यक्षों को निर्देश दिए कि वे किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने के लिए सक्रियता से कृषकों को प्रेरित कर उन्हें हर संभव सहायता करें। उन्होंने सभी एपीएमसी को प्राकृतिक पद्धति से उगाये गये गेहूं, मक्की और कच्ची हल्दी की खरीद के लिए हाई एंड साइलो स्थापित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक पद्धति से उगाई गई गेहूं की खरीद प्रक्रिया आरम्भ हो गई है और राज्य सरकार किसानों से गेहूं खरीद पर 60 रुपये प्रतिकिलो का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है। उन्होंने कृषि विभाग को प्राकृतिक खेती के लिए प्रदेश के किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज प्रदान करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकारी फार्मो को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत कृषि विभाग ने जिला कांगड़ा में भट्टू फार्म, जिला सिरमौर में भगाणी फार्म और जिला सोलन में बेरटी-बोच फार्म स्थापित किए हैं। आगामी समय में प्रदेश में इस तरह के और भी आदर्श फार्म स्थापित किए जाएंगे।

सुक्खू ने प्रदेशभर के विभिन्न स्थानों के निर्माणाधीन सीए स्टोर की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सीए स्टोर किसानों एवं बागवानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य प्रदान करने के लिए महत्त्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जिला शिमला के जुब्बल के अणु, चौपाल, संदासू खड़ापत्थर, दत्तनगर और ढली, जिला कांगड़ा के कंदरौरी और सुलह, जिला सोलन के जाबली, जिला किन्नौर के भावानगर और जिला मंडी के सुन्दरनगर में चरणबद्ध तरीके से सीए स्टोर स्थापित कर रही है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 330 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी 12 जिलों में 1010 करोड़ रुपये से कार्यान्वित की जा रही जाइका परियोजना की भी समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस परियोजना के अधिकाधिक लाभ प्रदेश के किसानों को सुनिश्चित किए जाएं। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड की विभिन्न परियोजनाओं की भी समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

इस अवसर पर प्रो. चन्द्र कुमार, विधायक चन्द्र शेखर, कृषि सचिव सी पालरासू, निदेशक कुमुद सिंह और एपीएमसी के अध्यक्ष उपस्थित थे।

राज्य के 50 विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित:स्वास्थ्य मंत्री

शिमला/शैल। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल ने विशेष उच्चाधिकार क्रय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि समिति पारदर्शी तरीके से विश्व स्तरीय स्वास्थ्य संबंधी मशीनरी और उपकरणों की खरीद सुनिश्चित करें, ताकि राज्य के लोगों को अत्याधुनिक और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य के लगभग 50 विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए गए हैं। इन स्वास्थ्य संस्थानों में छह-छह विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों को उच्च स्तरीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। यह संस्थान चरणबद्ध तरीके से सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे। नव स्थापित आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों सहित प्रदेश भर में सभी स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत करने के लिए अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि पर्याप्त और नवीनतम मशीनों से लैस होने के उपरान्त यह स्वास्थ्य संस्थान लोगों को गुणवत्तापूर्ण उपचार सुविधा प्रदान करने में मील पत्थर साबित होंगे। इससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए घरों से दूर या राज्य से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

समिति ने पांच फेको मशीनों की खरीद के लिए स्रोत और दरों को मंजूरी दे दी है। इससे लगभग 30 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाली फेको मशीनों की खरीद सुनिश्चित की जा सकेगी। समिति द्वारा पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा के लिए डिजिटल रेडियोग्राफी मशीन, हाई-रिजॉल्यूशन कलर डॉप्लर अल्ट्रासाउंड और डिजिटल मैमोग्राफी मशीन खरीदने की प्रक्रिया में और तेजी लाने के लिए संशोधनों को भी मंजूरी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों के लिए विभिन्न मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद के लिए तकनीकी उप-समिति की सिफारिशों को भी मंजूरी दी गई।

सचिव स्वास्थ्य एम. सुधा देवी, मुख्यमंत्री के सलाहकार अधोसंरचना और समिति के सह-सदस्य अनिल कपिल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

विक्रमादित्य सिंह ने की शहरी विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा

शिमला/शैल। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शहरी विकास विभाग के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में प्रधान सचिव शहरी विकास देवेश कुमार सहित शहरी विकास विभाग के अधिकारी तथा हिमाचल प्रदेश के विभिन्न शहरी निकायों के आयुक्तों, कार्यकारी अधिकारियों एवं सचिवों ने भाग लिया।

इस अवसर पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में 90:10 के अनुपात में चलाई जा रहीं केन्द्रीय और प्रदेश सरकार वितपोषित सभी योजनाओं को समयबद्ध क्रियान्वित करना सुनिश्चित बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इन विकास योजनाओं का समयबद्ध कार्यान्वयन से न केवल पात्र लोग लाभान्वित होंगे, बल्कि निर्धारित लक्ष्यों को भी समयबद्ध हासिल किया जा सकेगा।

शहरी विकास मंत्री ने कहा कि 5 फरवरी, 2025 को प्रदेशभर में स्वच्छ शहर, समृद्ध शहर अभियान को शुरू किया गया था। अढ़ाई माह तक चले इस अभियान का उद्देश्य जनभागीदारी सुनिश्चित बनाते हुए शहरी स्वच्छता व सतत् विकास को बढ़ावा देना रहा। इस अभियान के अंतर्गत नागरिक सेवा पोर्टल के तहत वार्ड स्तर पर समाधान शिविर लगाकर, नागरिकों को 9 आवश्यक सेवाएं प्रदान की गई।

उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस अभियान के तहत प्रदेश में सुन्दरनगर, सोलन, धर्मशाला व जुब्बल, जोगिन्दरनगर तथा पालमपुर व सुजानपुर शहरी निकायों ने क्रमश: प्रदेशभर में पहले पांच स्थानों पर रहकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है तथा बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरी निकायों को भविष्य में प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नागरिक सेवा पोर्टल के माध्यम से शुरू की गई नौ ऑनलाइन सेवाओं को 15 जून, 2025 से सभी प्रकार की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से ही पूरी की जाएगी। इस सम्बंध में आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए जाएंगे।

देवेश कुमार ने निर्देश दिए कि अगले 15 दिनों में एस्टेट शाखा को मजबूत किया जाएगा तथा सम्पत्ति मुद्रीकरण व अंडर परफार्मिंग परसम्पत्तियों के लिए पदनाम बार जिम्मेवारी निर्धारित की जाएगी। साथ ही कहा कि बकाया सम्पत्ति कर के प्रोत्साहन के लिए समर्पित योजना विभाग द्वारा तैयार की जाएगी। उन्होंने शहरी विभाग निदेशालय को सम्पत्ति कर की बिलिंग और संग्रह सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए कहा तथा वर्तमान प्रक्रिया में जहां जरूरी होगा, वहां रांची म डल पर विचार किया जाएगा।

बैठक में ड्रोन आधारित जीआईएस मेपिंग और प्रापर्टी सर्वे में एजीआईएसएसी द्वारा की गई पगति की समीक्षा की तथा मामले की तत्कालिता को ध्यान में रखते हुए प्रगति में तेजी लाने के लिए एजीआईएसएसी के साथ बैठक की जाएगी।

उद्योग मंत्री ने बल्क ड्रग पार्क परियोजना प्रगति की समीक्षा की

शिमला/शैल। उद्योग मंत्री, हर्षवर्धन चौहान ने बल्क ड्रग पार्क इंफ्रास्टक्चर लिमिटेड (एचपीबीडीपी आईएल) की उच्च स्तरीय समिति (एचपीसी) की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने पिछली बैठक में लिये गये प्रमुख निर्णयों पर की गई कारवाई की समीक्षा की।

हिमाचल प्रदेश बल्क ड्रग पार्क इंफ्रास्टक्चर लिमिटेड ने साइट विकास और आतंरिक सड़कों के निर्माण के लिए लगभग 287 करोड़ रुपये की निविदा जारी की है। समिति द्वारा वर्चुअल माध्यम से जुड़े विभिन्न बोलीदाता कम्पनियों द्वारा उठाये गये प्रश्नों का समाधान किया गया। इसके साथ ही बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 मई, 2025 तक करने का निर्णय लिया ताकि इच्छुक कम्पनियों को तैयारी करने के लिये अधिक समय मिल सके।

उद्योग मंत्री ने बल्क ड्रग पार्क के निर्माण के लिए शून्य तरल अपशिष्ट (जेडएलडी) सामान्य अपशिष्ट, बॉयलर स्टीम जेनरेशन और वितरण प्रणाली तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसी शेष निविदाओं को शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए।

उन्होंने सभी हितधारक विभागों को इस मेगा परियोजना को समयबद्ध पूर्ण करने के लिए निमार्ण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

निदेशक उद्योग एवं बल्क ड्रग पार्क राज्य क्रियान्वयन एजेंसी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. युनूस ने इस सम्बंध में हुई प्रगति पर विस्तृत प्रस्तुति दी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी. नजीम, एचपीएसआईडीसी के प्रबंध निदेशक राजश्वर गोयल, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तिलक राज शर्मा और अन्य सम्बंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे।

यदि धैर्य का कोई मूल्य है, तो वह समय के अंत तक बना रहना चाहिए।

.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

ऑपरेशन सिंदूर के बाद उठे सवालों का जवाब कब आयेगा?

पहलगाम की आंतकी घटना के बाद पूरे देश में आतंकवाद के खिलाफ भयंकर रोष था। इस आतंकवाद को सीमा पार से संचालित करार दिये जाने के बाद पूरे विपक्ष ने सरकार को खुला समर्थन देते हुये इससे निपटने के लिये प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया। बल्कि जब सरकार ने इस पर जवाबी कारवाई करने में कुछ समय लगा दिया तब इस देरी के लिए प्रश्न भी पूछे गये। अन्त में सरकार ने सैन्य कारवाई करने का फैसला लिया। पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया। इस कारवाई में सेना ने जो समझ और साहस दिखाया उस पर पूरे देश ने गर्व महसूस किया। लेकिन इस शुरुआत के चौथे दिन ही जब इसमें सीज फायर घोषित कर दी गयी तब देश को इस पर आश्चर्य हुआ क्योंकि भारतीय सेना इसमें लगातार सफल होती जा रही थी तब ऐसे में भारत द्वारा इस सीज फायर की घोषणा करना या इस पर सहमत होना अटपटा सा लगा। लेकिन जब इस युद्ध विराम का श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिया और इसकी सूचना भी भारत से पहले दे दी तब से पूरी स्थितियों में एक मोड़ आ गया है। क्योंकि ट्रंप ने इस दखल का तीन बार अपने ब्यानों में श्रेय ले लिया। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने जब सीज फायर के बाद देश को संबोधित किया तब उन्होंने एक बार भी अपने संबोधन में ट्रंप का जिक्र तक नहीं किया है विपक्ष ने इस पर सर्वदलीय बैठक बुलाने या संसद का सत्र बुलाकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है लेकिन सरकार ऐसा नही कर रही है। अपने देश और संसद के सामने स्थिति स्पष्ट करने की बजाये सरकार ने सांसदों का एक डेलीगेट विभिन्न देशों में भेजने का निर्णय लिया जो वहां पर भारत का पक्ष रखेंगे।

ऐसे में यह सवाल खड़ा हो गया है देश और संसद या सर्वदलीय बैठक में स्थिति स्पष्ट करने की बजाये विदेशों में अपना पक्ष रखने का विकल्प क्यों चुना गया। क्योंकि जब आई.एम.एफ. ने पाकिस्तान को एक बिलियन डॉलर का ऋण पहलगाम की घटना के बाद स्वीकार किया तब एक देश ने इसका विरोध नहीं किया। जबकि इस कमेटी में भारत समेत पच्चीस देश सदस्य थे। भारत ने इसके विरोध में मतदान करने की बजाये बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। किसी भी देश का समर्थन इस बैठक में हासिल क्यों नहीं कर पाया इसका जवाब भारत कैसे देगा? भारत-पाक के रिश्ते इस आतंक को लेकर तो देश के विभाजन के बाद से ही बिगड़ने शुरू हो गये थे। हर आतंकी घटना में पाक की परोक्ष/अपरोक्ष में भूमिका रही है। फिर प्रधानमंत्री मोदी पिछले ग्यारह वर्षों में इस विषय पर अन्तरराष्ट्रीय समुदाय को क्यों नहीं समझा पाये हैं? जबकि भारत तो विश्व गुरु होने का दावा करता आया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और उनके परिवार को ट्रोल किया गया उसका क्या जवाब है? कर्नल सोफिया कुरैशी को जिस भाषा में मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह ने अपशब्द कहे हैं उसका अदालत ने तो कड़ा संज्ञान ले लिया लेकिन भाजपा संगठन की इस बारे में आज तक खामोशी का क्या जवाब है। प्रधानमंत्री इस ट्रोल पर क्यों खामोश हैं?

अभी जो सांसद विदेश डैलीगेशन में भेजे जा रहे हैं उनके चयन में उनके दलों को विश्वास में क्यो नहीं लिया गया? जो नाम दलों ने भेजे उनकी जगह सरकार ने दूसरे ही लोगों का चयन क्यों कर लिया? क्या इसमें दलों की सहमति नहीं रहनी चाहिये थी। क्या इसे राजनीति के आईने में नही देखा जायेगा। जब विदेश में इस ट्रोल को लेकर पूछा जायेगा तो क्या जवाब दिया जायेगा? क्योंकि यह वीडियोज तो पूरे विश्व में देखे जा रहे होंगे। पाक पर कारवाई का विदेश मंत्री का वीडियो जिसमें वह कह रहे हैं कि हमने हम्लों की सूचना पहले ही पाकिस्तान को दे दी थी। इसका क्या जवाब दिया जायेगा। आज सबसे पहले अपने देश की जनता, सभी राजनीतिक दलों और संसद के सामने सारी स्थितियां स्पष्ट की जानी चाहिये थी क्योंकि पूरा देश सरकार और सेना के साथ खड़ा रहा है। इसलिये ऑपरेशन सिंदूर के बाद उठे सवालों पर यहां जवाब दिया जाना आवश्यक हो जाता है।

महिलाएं आत्मनिर्भर हिमाचल की संकल्पना को साकार करने में दे रही अहम योगदान

प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। सरकार की ओर से मिले प्रोत्साहन एवं स्वयं की मेहनत से ग्रामीण स्तर पर महिलाएं अब आत्मनिर्भर हिमाचल की संकल्पना को साकार करने में अपना अहम योगदान दे रही हैं। इन्हीं में से एक हैं, रक्षा देवी। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी रक्षा देवी कभी एक गृहिणी के तौर पर सामान्य रूप से अपना जीवन यापन कर रही थीं। सरकार से मिली मदद एवं मार्गदर्शन ने उनके जीवन की धारा ही बदल दी। आज वे एक सफल उद्यमी के रूप में कार्य कर रही हैं और तीन अन्य महिलाओं को रोजगार भी दिया है।

बल्ह घाटी के मैरमसीत क्षेत्र में बैरी गांव की रक्षा देवी ने बताया कि पहले वह एक गृहिणी थीं। शीतला स्वयं सहायता समूह की सदस्य बनने के बाद उन्होंने अपने हुनर को पहचाना। सरकार के प्रोत्साहन से इन समूहों से जुड़कर महिलाएं घर-द्वार पर ही उत्पाद तैयार कर अपनी आजीविका कमा सकती हैं। उन्होंने बताया कि मोटे अनाज के उत्पाद जैसे मल्टीग्रेन कचौरी, मल्टीग्रेन सिद्दू, कोदरे की चाय और मिठाइयां इत्यादि बनाने का प्रशिक्षण उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर से मिला है। इसी बीच उनके गांव में हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-जाईका-(जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी) शुरू हुई। रक्षा देवी ने बताया कि वह केवीएम की प्रधान भी हैं।

बकौल रक्षा देवी उनका समूह अपने हाथों से मल्टीग्रेन आटा, कोदरे, जौ, चावल तथा ज्वार का आटा, लोकल चावल, लाल चावल, अलसी, लोकल सीरा, क्राफ्ट तथा बहुत सा हैंडमेड सामान तैयार करता है। इसके अलावा हम कचौरी ऑर्डर पर या रोजाना दुकान पर

भी बनाते हैं। उनका दावा है कि उनके उत्पाद प्राकृतिक खेती से तैयार किए गए हैं जो कि जहर मुक्त हैं और स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हैं।

एसडीएम कार्यालय सुंदरनगर के समीप स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों की बिक्री के उद्देश्य से जाईका के तहत रिटेल आउटलेट शीतला स्वयं सहायता समूह की सदस्य रक्षा देवी को दिया गया। इस समूह का गठन खंड परियोजना प्रबंधन इकाई (बीपीएमयू) मंडी के तहत किया गया है। समूह मुख्य रूप से बाजरा उत्पादों जैसे लद्दू और पंजीरी और स्थानीय रूप से बने उत्पादों जैसे अचार, चटनी, स्क्वैश, घी, शहद और मक्का, ज्वार, धान, रागी के आटे और हस्तशिल्प पर काम कर रहा है। स्व-निर्मित उत्पादों की खरीद के लिए प्रदेश भर के लगभग 15 अन्य समूहों के साथ भी जुड़ा है। वर्तमान में रिटेल आउटलेट से प्रतिमाह लगभग एक लाख रुपए की आमदनी हो रही है।

सितंबर, 2024 से समूह ने मोटे अनाज के खाद्य पदार्थ जैसे सिद्दू, चाय और कचौरी बनाना भी शुरू किया है। खाद्य पदार्थो के प्रति ग्राहकों की भारी मांग को देखते हुए शीतला स्वयं सहायता समूह हर सोमवार और गुरुवार को सरसों का साग और मक्की की रोटी तथा राजमाह-चावल तैयार कर रहा है। न्यायालय, सरकारी अस्पताल सुंदरनगर, आत्मा कृषि परियोजना, पुलिस स्टेशन के कर्मचारी नियमित आधार पर बिक्री दुकान पर आते हैं। उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में दैनिक ग्राहकों से बहुत सराहनीय प्रतिक्रिया मिल रही है। गुणवत्ता बनाए रखने और सुधारने में समूह की दक्षता के परिणामस्वरूप ही व्यापक बाजार और ग्राहकों में बढ़ोतरी हो रही है।

प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हुए रक्षा देवी ने कहा कि रिटेल आउटलेट से हम अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रिटेल आउटलेट में तीन महिलाएं काम कर रही हैं जिनके लिए भी रोजगार का रास्ता खुल गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न गांवों से भी महिलाएं घर पर ही उत्पाद बनाने का काम कर रही हैं, उनके लिए भी रोजगार का साधन बना है।

छात्रवृत्ति योजनाओं से 87 हजार से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित

शिमला। हिमाचल प्रदेश शिक्षा क्षेत्र अभूतपूर्व बदलाव के दौर से गुजर रहा है। शिक्षा में समावेशिता, अकादमिक उत्कृष्टता और संरचनात्मक सुधारों के दृष्टिगत अनेक क्रांतिकारी बदलाव लाकर इस क्षेत्र को पुनः परिभाषित किया जा रहा है। वर्तमान प्रदेश सरकार सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है ताकि हर बच्चे के उज्ज्वल भविष्य का सपना साकार हो।

पिछले अढ़ाई वर्षो में सरकार ने छात्रवृत्ति कार्यक्रमों को व्यापक विस्तार दिया है। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से 87,000 से अधिक विद्यार्थियों को लगभग 92 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। यह योजनाएं सामाजिक रूप से कमजोर वर्गो जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के बच्चों के गुणात्मक शिक्षा के सपने को साकार करने में मील पत्थर साबित हो रही हैं।

राज्य में इन कल्याणकारी योजनाओं के तहत हजारों विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति से लाभान्वित किया गया। प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत उच्च शिक्षा और वंचित वर्गो के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। इसका लाभ उठाकर बच्चे सैनिक स्कूल सुजानपुर टीहरा और आरआईएमसी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में चयनित होने में सफल हुए हैं। पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति के 22,500 से अधिक विद्यार्थियों को 4,049.70 लाख रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। इसके अलावा, प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति का लाभ प्रदान किया जा रहा है ताकि समावेशी शिक्षा के लक्ष्य हासिल किए जा सकें।

सरकार द्वारा उठाए गए ठोस प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। जनवरी, 2025 में जारी शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, हिमाचल प्रदेश पढ़ने और सीखने के स्तर की राष्ट्रीय रैंकिंग में 21वें स्थान से शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। रिपोर्ट में हिमाचल के विद्यार्थियों को पढ़ने के कौशल के लिए देश भर में शीर्ष पर रखा गया है। प्रदेश में किए गए जा रहे सर्वेक्षण भी सीखने के परिणामों में उल्लेखनीय सुधार को प्रदर्शित कर रहे हैं। केंद्र सरकार की पीएमश्री योजना को सफलतापूर्वक लागू करने में हिमाचल, देश भर में शीर्ष स्थान पर रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा योजना के तहत उपलब्ध धनराशि का शत प्रतिशत उपयोग भी सुनिश्चित किया गया है।

शिक्षा क्षेत्र में की जा रही अभिनव पहलों की इस श्रृंखला के तहत प्रदेश सरकार ने पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा उपलब्ध करवाने के वायदे को पूरा किया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं, इन स्कूलों के माध्यम से बच्चों को वैश्विक स्तर की शिक्षा प्रदान करने के ध्येय से पूर्ण किया जाएगा। धन की कमी से प्रदेश की युवा प्रतिभा उच्च शिक्षा से वंचित न रह जाए यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने डॉ. वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना शुरू की है। इस योजना को विस्तार प्रदान करते हुए अब देश के बाहर शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक युवाओं को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। विधवा, निराश्रित और तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों के साथ-साथ दिव्यांग माता-पिता के बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की गई है।

बच्चों और शिक्षकों को वैश्विक शिक्षा पद्धति से अवगत करवाने के लिए सरकार ने सिंगापुर, कंबोडिया और शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी राज्य केरल और अन्य राज्यों में मेधावी विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए एक्सपोजर विजिट की सुविधा प्रदान की जा रही है ताकि उनका ज्ञानवर्धन हो सके। सरकार के इन प्रयासों को केन्द्र सरकार द्वारा भी सराहा गया है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार के लिए यूनेस्को के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित किया है। इस सहयोग का मुख्य उद्देश्य पाठयक्रम और शिक्षण पद्धति को आधुनिक बनाना, मूल्यांकन की पद्धति में सुधार करना और विद्यार्थियों को 21वीं सदी के कौशल में निपुण बनाना है।

नीति, निवेश, नवाचार और समावेश के समग्र मिश्रण से, राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र का कायाकल्प किया है। सपनों को पूरा करने वाली छात्रवृत्तियों से लेकर शैक्षणिक अधोसंरचना में सुधार के साथ-साथ प्रदेश सरकार ने यह साबित किया है कि गुणात्मक शिक्षा केवल विशेष वर्गो तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह हर एक बच्चे का अधिकार है। बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान कर सरकार न्यायपूर्ण, प्रबुद्ध और समृद्ध समाज की नींव रख रही है।

पीएम–जनमन भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल

शिमला। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव विभु नायर ने आवश्यक सेवाओं के संचालन और प्रभावी वितरण पर विशेष ध्यान देने के साथ पीएम-जनमन के तहत विभिन्न पहलों को फिजिकल रूप से पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया। नायर ने कहा कि राज्य अपनी-अपनी योजनाओं का उपयोग जहां भी संभव हो, इन पहलों को समर्थन देने और उन्हें प्राप्त करने के लिए करें तथा सभी पहलों के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये जाने चाहिए। नई दिल्ली में पीएम-जनमन की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पीएम-जनमन के कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर शत-प्रतिशत परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रत्येक माह के अंतराल पर ऐसी समीक्षा आयोजित की जाएगी।

एक दिवसीय समीक्षा बैठक के दौरान, अभियान के अंतर्गत बुनियादी ढांचे (व्यक्तिगत और सामुदायिक परिसंपत्तियों) के तेजी से और मिशन मोड में पूरा होने से संबंधित प्रमुख पहलुओं पर चर्चा की गई, जिसमें सेवा सम्पूर्णता को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयासों में सामंजस्य स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रतिभागियों ने संभावित कार्यान्वयन बाधाओं की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए विचार-मंथन सत्रों में भाग लिया। यह भी देखा गया कि समय पर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के भीतर कई स्तरों पर एक व्यवस्थित और नियमित समीक्षा तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए और विभागों के बीच समन्वय को गांव स्तर तक दोहराया जाना चाहिए।

चर्चा के मुख्य बिन्दु इस बात पर केंद्रित थे कि सभी गांवों में अभियान के तहत रेखांकित पहलों का पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

- स्वास्थ्य, आंगनवाड़ी और कौशल विकास की आवश्यक सेवाओं के साथ बहुउद्देशीय केंद्रों (एमपीसी) का निर्माण पूरा करना और उनका संचालन शुरू करना।
- सभी वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) में व्यावसायिक गतिविधियों की शुरुआत
- पक्के मकानों की स्वीकृति और निर्माण का फिजिकल कार्य पूरा करना तथा आधार जैसे आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- बस्तियों के स्थान के अनुसार सड़कों की सफाई और चल रही सड़क परियोजनाओं को समय पर पूरा करना
- सभी आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) का संचालन और निगरानी
- जीपीएस जैसे तकनीकी उपकरणों के उपयोग से मोबाइल मेडिकल यूनिटों (एमएमयू) के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी को मजबूत करना।
- लक्षित संख्या में पीवीटीजी छात्रावासों की स्वीकृति और निर्माण
- ऑन-ग्रिड या ऑफ-ग्रिड समाधानों के माध्यम से पीवीटीजी घरों का विद्युतीकरण
- नल जल आपूर्ति द्वारा गांवों का सम्पूर्ण कवरेज
- दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए मोबाइल टावरों की स्थापना

प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) योजना के सम्पूर्णता स्तरों का आकलन करने के उद्देश्य से जनजातीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में इस समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इसमें पीएम-जनमन मिशन में भाग लेने वाले 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जनजातीय कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव/सचिव स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में भाग लेने वाले मंत्रालयों के अधिकारी भी शामिल हुए।

प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के व्यापक विकास और कल्याण को सुनिश्चित करना है। 2023 में जनजातीय गौरव दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित यह अभियान देश में सबसे अधिक वंचित समुदायों के लिए समावेशी विकास और सामाजिक न्याय के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है जो विकसित गांव, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेगा।

अभियान को राज्य सरकारों के सहयोग से 9 मंत्रालयों और विभागों के समन्वित प्रयासों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इससे संबंधित फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा करने और समयबद्ध तरीके से सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रित, मिशन-मोड दृष्टिकोण अपनाया गया है।

आयुर्वेद दिवस हर वर्ष 23 सितंबर को मनाया जाएगा

शिमला। वैश्विक दृश्यता और पालन में निरंतरता को बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय में 23 सितंबर को प्रत्येक वर्ष आयुर्वेद दिवस मनाने के लिए निर्धारित किया है। 23 मार्च 2025 को जारी राजपत्र अधिसूचना के जरिये यह बदलाव लागू किया गया है, जो पहले धनतेरस के दिन आयुर्वेद दिवस मनाने प्रथा से एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जो चंद्र कैलेंडर के आधार पर परिवर्तनशील था।

आयुर्वेद दिवस को हर साल आयुर्वेद को एक वैज्ञानिक साक्ष्य-आधारित और समग्र चिकित्सा प्रणाली के रूप में बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता रहा है, जो निवारक स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब तक, आयुर्वेद दिवस धनतेरस के साथ मनाया जाता था, जो हिंदू मास कार्तिक (आमतौर पर अक्तूबर या नवंबर) में पड़ता है। हालांकि, धनतेरस की तारीख हर साल बदलती रहती थी, जिसके कारण आयुर्वेद दिवस की तारीख निश्चित नहीं थी।

आयुष मंत्रालय ने यह भी उल्लेख किया कि अगले दशक में धनतेरस की तारीख 15 अक्तूबर से 12 नवंबर के बीच व्यापक रूप से बदलती रहेगी, जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजनों को करने में तार्किक चुनौतियां उत्पन्न होंगी।

इस असंगति को दूर करने और राष्ट्रीय व वैश्विक उत्सवों के लिये एक स्थिर संदर्भ बिंदु स्थापित करने के लिए आयुष मंत्रालय ने उपयुक्त विकल्पों की जांच के लिए एक समिति गठन किया। विशेषज्ञ पैनल ने चार संभावित तारिखों का प्रस्ताव रखा, जिसमें 23 सितंबर की तारीख सर्वश्रेष्ठ विकल्प के रूप में सामने आयी। यह निर्णय व्यावहारिक और प्रतीकात्मक दोनों विचारों पर आधारित था।

चुनी गई तारीख 23 सितंबर, शरद विषुव के साथ मेल खाती है, जब दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। यह खगोलीय घटना प्रकृति में संतुलन का प्रतीक है, जो आयुर्वेद दर्शन के साथ पूर्ण रूप से मेल खाती है, जो मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन पर जोर देता है। विषुव, ब्रह्मांडीय सामंजस्य का प्रतिनिधित्व करता है, आयुर्वेद के सार को रेखांकित करता है-प्रकृति के साथ संतुलन में जीना।

आयुष मंत्रालय व्यक्तियों, स्वास्थ्य पेशेवरों, शैक्षणिक निकायों और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों से आग्रह करता है कि वे नवनिर्धारित तारीख को अपनाएं और प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस समारोह में सक्रिय रूप से भाग लें। मंत्रालय इस बदलाव को आयुर्वेद को वैश्विक स्वास्थ्य नैरेटिव में और अधिक समाहित करने तथा इसके निवारक और स्थाई स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के रूप में कालातीत मूल्य को बढ़ावा देने के अवसर के रूप में देखता है।

भारतीय वैज्ञानिकों ने तेजी से चार्ज होने वाली और लंबे समय तक चलने वाली सोडियम-आयन बैटरी डिजाइन की

शिमला। कारों से लेकर गांवों तक विद्युतीकरण की दिशा में तेजी से बढ़ती दुनिया में एक चीज सबसे महत्वपूर्ण बनी हुई है: किफायती, तेज और सुरक्षित बैटरी। हालांकि लिथियम-आयन बैटरी अब तक इस क्रांति को गति देती रही है, लेकिन वे महंगी हैं। इसके अलावा, लिथियम संसाधन अल्प मात्रा में हैं और

भू-राजनीतिक रूप से सीमित हैं, लेकिन बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने शायद एक शक्तिशाली विकल्प ढूंढ लिया है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के स्वायत्त संस्थान जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र (जेएनसीएएसआर) की एक शोध टीम ने नासिकोन-प्रकार के कैथोड और एनोड सामग्री पर आधारित एक सुपर-फास्ट चार्जिंग सोडियम-आयन बैटरी (एसआईबी) विकसित की है, जो केवल छह मिनट में 80 प्रतिशत तक चार्ज हो सकती है और 3000 से अधिक चार्ज साइकिल्स तक चल सकती है।

पारंपरिक एसआईबी, जो धीमी चार्जिंग और कम समय तक चलती है, के विपरीत यह नई बैटरी रसायन विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी के एक बुद्धिमत्तापूर्ण मिश्रण का उपयोग करती है। प्रो. प्रेमकुमार सेनगुट्टुवन और पीएचडी डिग्रीधारक बिप्लब पात्रा के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने एनोड के लिए एक नई सामग्री तैयार की-$Na_{1.0}V_{0.25}Al_{0.25}Nb_{1.5}(PO_4)_3$- और इसे तीन महत्वपूर्ण तरीकों से अनुकूलित किया-कणों को नैनोस्केल तक सिकोड़ा, उन्हें एक पतली कार्बन परत में लपेटा और निम्न मात्रा में एल्युमीनियम डालकर एनोड सामग्री में सुधार किया। इन बदलावों ने सोडियम आयनों को अधिक तेजी से और अधिक सुरक्षित रूप से आगे बढ़ने में सक्षम बनाया, जिससे गति और टिकाऊपन दोनों में वृद्धि हुई।

भारत में सोडियम किफायती और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जबकि लिथियम दुर्लभ है और व्यापक रूप से इसका आयात किया जाता है। लिथियम के बजाये सोडियम के माध्यम से बनी बैटरी देश को ऊर्जा भंडारण प्रोद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनने में मदद कर सकती है-जो भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत मिशन का एक प्रमुख लक्ष्य है।

लागत के अतिरिक्त, ये सोडियम-आयन बैटरियां इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर ग्रिडों से लेकर ड्रोन और ग्रामीण घरों तक सभी को ऊर्जा प्रदान कर सकती हैं, जिससे स्वच्छ ऊर्जा उन स्थानों पर उपलब्ध हो सकेगी जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

इस प्रोद्योगिकी का परीक्षण और सत्यापन इलेक्ट्रोकेमिकल साइकलिंग और क्वांटम सिमुलेशन सहित उच्च-स्तरीय विधियों के माध्यम से किया गया है। विशेष बात यह है कि यह न केवल तेजी से चार्ज करने में सहायक है, बल्कि सामान्य बैटरियों के विपरीत यह आग लगने और खराब होने के जोखिम से भी बचाती है।

हालांकि इन बैटरियों को बाजार में आने से पहले और अधिक अनुसंधान एवं विकास की आवश्यकता है, लेकिन यह खोज भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अन्य वैज्ञानिकों ने भी इस पर ध्यान देना आरंभ कर दिया है और निरंतर समर्थन के साथ, हम शीघ्र ही भारत को ग्रीन बैटरी प्रोद्योगिकी में वैश्विक रूप से अग्रणी स्थिति में देख सकते हैं।

भविष्य के सपनों में आशा की किरण बनकर उभर रही इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना

शिमला। हम मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के अत्यन्त आभारी है। उनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप अब हमारे बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त करके अपने सपनों को साकार कर पा रहे हैं। ऊना जिला की आशा पुरी ने इंदिरा

गांधी सुख शिक्षा योजना के बारे में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आभार प्रकट करते हुए कहा कि हम ऐसी सरकार बार-बार देखना चाहते हैं। आशा ने करीब पांच साल पहले अपने बेटे को खो दिया था। तब से वह अपनी बहू और दो पोतियों के साथ रह रही हैं। परिवार को लड़कियों की पढ़ाई का खर्च वहन करना तो दूर अपने दिनचर्या के खर्चे उठाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे कठिन समय में इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना उनके लिए उम्मीद की किरण बनी।

आशा की बहू पूजा पुरी का कहना है कि पति की मृत्यु के बाद परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था। बच्चों की शिक्षा जारी रखना बहुत कठिन हो गया था। हमने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत आवेदन किया और अब दोनों बेटियां राज्य सरकार से मासिक आर्थिक सहायता प्राप्त कर रही है। राज्य सरकार द्वारा उन्हें प्रतिमाह 1000-1000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

इसी तरह चंबा जिले की दूरस्थ पांगी घाटी के लुज गांव की वर्षा ने वर्ष 2014 में अपने पिता को खो दिया था। उनके पिता की मृत्यु के बाद परिवार की आय का मुख्य स्रोत समाप्त हो गया था, क्योंकि उनके पिता ही परिवार के अकेले कमाने वाले व्यक्ति थे। वर्षा का कहना है कि पिता की मृत्यु के पश्चात मेरी मां शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकी। मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करते हुए वर्षा ने कहा कि इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना की मदद से अब हमें वित्तीय सहायता मिल रही है और मैं पढ़ाई कर पा रही हूं।

आर्थिक सहायता से कहीं बढ़कर इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए बेहतर भविष्य की नई राहें खोल रही है। यह योजना उन बच्चों के लिए वरदान बनी है जो पारिवारिक या सामाजिक कारणों से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।

मुख्यमंत्री की कल्याणकारी सोच इस योजना के माध्यम से शिक्षा की पहुंच को व्यापक बना रही है। इस योजना के तहत विधवा, बेसहारा, परित्यक्त महिलाओं या दिव्यांग माता-पिता के 18 वर्ष तक के बच्चों को उनकी मूलभूत शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिमाह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। उच्च शिक्षा के लिए, सरकारी संस्थानों में डिग्री, डिप्लोमा या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकित 18 से 27 वर्ष की आयु के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा रही है। छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में पीजी आवास के लिए 3,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्तमान में 18 वर्ष तक की आयु के 21,288 बच्चे तथा 18 से 27 वर्ष की आयु तक के 3,347 विद्यार्थियों को इस योजना के तहत लाभार्थी के रूप में चिन्हित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान लगभग 28.23 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस योजना की पात्रता के लिए आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए तथा परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

पशुपालन विभाग में पशु मित्र के 1,000 पद भरे जाएंगे

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पशु मित्र नीति-2025 को मंजूरी दी गई। इस नीति के अंतर्गत पशुपालन विभाग में मल्टी टास्क वर्कर (पशु

मित्र) के 1,000 पद भरे जाएंगे।

बैठक में स्कूलों में पुस्तकालयों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (पुस्तकालय) के 100 पद भरने को मंजूरी दी गई।

इसके अतिरिक्त, राजस्व विभाग में वरिष्ठ सहायक के 10 पद तथा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 15 पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, हमीरपुर में विभिन्न श्रेणियों के पांच पद भरने को भी मंजूरी दी।

आयुष विभाग में बैचवाइज आधार पर आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारी के पांच पद भरने का निर्णय लिया गया है।

राज्य के गौ सदनों में गौवंश के लिए चारा पर दिए जाने वाले अनुदान को प्रति गौ वंश 700 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रतिमाह करने का फैसला लिया गया।

मंत्रिमंडल ने ऑपरेशन थियेटर सहायकों के मासिक मानदेय को 17,820 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने तथा रेडियोग्राफरों व एक्स-रे तकनीशियनों के मासिक मानदेय को 13,100 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का निर्णय लिया है।

राज्य में क्षरित वन क्षेत्रों में कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के तहत निजी उद्यमियों द्वारा वृक्षारोपण के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन अडॉप्शन योजना को मंजूरी दी गई।

बैठक में नगर निगम शिमला में घाटी की ओर भवनों के निर्माण को प्रतिबंधित करने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन नियम, 2014 में संशोधन को मंजूरी दी गई। घाटी के सौन्दर्यीकरण को संरक्षित रखने के लिए नए प्रावधान के अनुसार निर्माण कार्य सड़क स्तर से कम से कम एक मीटर नीचे होने चाहिए।

मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला में माता तारा देवी मंदिर के साथ लगते वन क्षेत्र को शिमला विकास योजना के तहत हरित क्षेत्र के अंतर्गत लाने का भी निर्णय लिया है ताकि इस क्षेत्र का सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके।

बैठक में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना-2023 के तहत ई-टैक्सियों को किराए पर लेने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करने को भी स्वीकृति दी गई।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में डिजाइन विंग का सिविल विंग में विलय करने पर अपनी सहमति प्रदान की। इससे विभाग की कार्यशैली सुव्यवस्थित और दक्ष होगी।

बैठक में कुल्लू जिले के निरमंड विकास खंड में पशु चिकित्सा औषधालय सराहन का नाम बदलकर पशु चिकित्सा औषधालय बागा-सराहन करने को भी मंजूरी प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री ने वर्चुअली हमीरपुर जिला की विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से जिला हमीरपुर के अधिकारियों

के साथ बैठक की अध्यक्षता कर विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जिला में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि इन्हें समयबद्ध पूरा किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को बेसहारा जानवरों से जुड़ी समस्या का समाधान करने व किसानों को राहत देने के लिए गौ-अभ्यारण्य के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने के निर्देश दिए। उन्होंने हमीरपुर-घुमारवीं, नादौन-अम्ब तथा भोटा-ऊना सड़कों के किनारे ई-चार्जिंग व्हीकल स्टेशन स्थापित करने के लिए स्थान चिन्हित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में इलैक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए संबंधित अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नादौन ब्लॉक की ग्राम पंचायत हरेटा में 7 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले इको टूरिज्म परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस परियोजना के तहत पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी अधोसंरचना, घास के मैदान, नाइट कैपिंग के लिए ट्री हाउस, वॉकिंग एवं नेचर ट्रेल, कैफेटेरिया और चिल्ड्रन पार्क का विकास किया जाएगा।

बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचयाती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह शिमला में उपस्थित रहे तथा उपायुक्त हमीरपुर अमरजीत सिंह व अन्य वरिष्ठ अधिकारी हमीरपुर से वर्चुअली जुड़े।

सरकार सहासिक पर्यटन को दे रही व्यापक प्रोत्साहन:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने रिज से हिमालयन एडवेंचर स्पोर्ट्स एण्ड टूरिज्म प्रमोशन एसोसिएशन द्वारा हिमाचल टूरिज्म, हीट्रेक्स टायर्ज और हिमाचल प्रदेश साइकलिंग एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित एमटीबी हिमालया साइकिल रेस के 12वें संस्करण को झंडी दिखाकर रवाना किया।

यह रेस 'प्रोलॉग-हेरीटेज राइड रिज-आईआईएएस-रिज, कुफरी-चायल एक्ससीएम, शिमला-समरहिल-पोटर्ज हिल एक्ससीओ मार्ग से होते हुए 18 मई, 2025 को सम्पन्न होगी। इस प्रतियोगिता में देश भर से 100 से अधिक साइकिल सवार हिस्सा ले रहे हैं जिनमें राष्ट्रीय चौम्पियन और विश्वस्तरीय साइकलिस्ट भी शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के आयोजन राज्य की समृद्ध परम्परा, विरासत और संस्कृति को विश्व पटल पर प्रदर्शित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में साइकलिंग का बड़ा महत्त्व है। यह न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है बल्कि यह एक स्वच्छ, प्रदूषण रहित, मोटर चालक रहित परिवहन का साधन भी है। इसके अलावा यह रोमांच, फिटनेस और खेल गतिविधियों का एक बेहतरीन माध्यम है।

सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार

साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए गम्भीरता से प्रयास कर रही है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर साइकलिंग ट्रैक की पहचान की जा रही है जिनमें से कुछ शिमला में भी बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शिमला में 37 करोड़ रुपये की लागत से एक आइस्केटिंग रिंक बनाया जा रहा है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा शिमला के सर्कुलर रोड को चौड़ा किया जा रहा है, जिससे शहर में यातायात की समस्या को दूर करने में सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में हिमाचल ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य बन कर उभरेगा। सोलन जिले के नालागढ़ में ऑयल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से एक मेगावाट क्षमता वाला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी एक वर्ष के भीतर हिमाचल में केवल हरित ऊर्जा का ही उपयोग किया जाएगा।

इस अवसर पर विश्व चैम्पियन लक्ष्य जांगीड़ और आर्मी बैंड ने साइकलिंग शो की शानदान प्रस्तुति दी।

हिमालयन एंडवेंचर स्पोर्ट्स एण्ड टूरिज्म प्रमोशन एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहित सूद ने मुख्यमंत्री का इस आयोजन के शुभारम्भ के लिए अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आभार व्यक्त किया।

विकास परियोजनाओं को तेजी से क्रियान्वित कर रही सरकार:विक्रमादित्य

शिमला/शैल। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि लोक निर्माण और शहरी विकास विभागों के तहत विकासात्मक परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिये व्यापक रणनीति अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि शहरी विकास विभाग, पीडब्ल्यूडी और नाबार्ड के वरिष्ठ अधिकारियों, इंजीनियरों और कार्यकारी अधिकारियों

के साथ हाल ही में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चरण-4 के तहत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अपलोड करने में देश में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि राज्य 1500 किलोमीटर सड़क निर्माण के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में कार्य कर रहा है और इसके लिए स्थानीय समुदायों और पंचायतों से पूर्ण सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि समय पर भूमि की उपलब्धता और स्थानीय सहयोग के अभाव में लक्ष्य को 400 से 500 कि.मी. तक हासिल किया जा सकता है।

वन विभाग की मंजूरी में देरी और विभाग के नाम पर भूमि का पंजीकरण न होने जैसी प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभागों के साथ एक संयुक्त बैठक की योजना बनाई जा रही है। स्थानीय प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन की भागीदारी से भूमि की पहचान और अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी।

परियोजनाओं के कार्यान्वयन में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लोक निर्माण विभाग के डिवीजनों को लाल, पीला, हरा और गैर-निष्पादित, चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ आरोप पत्र तय करने और ब्लैक लिस्ट में डालने सहित सख्त कारवाई अमल में लाई जाएगी।

विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि शहरी विकास विभाग के तहत शहरी चुनौती निधि के तहत 1200 करोड़ रुपये की परियोजनाएं प्रस्तावित है जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से 25 प्रतिशत धनराशि तथा शेष राशि बैंकों और बाजार के माध्यम से जुटाई जाएगी। इसके अंतर्गत स्वच्छता, जल निकासी, पार्किंग सुविधाएं और शहरी बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण प्राथमिकता में शामिल हैं।

मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा प्रदान करने के लिए वह शीघ्र ही केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट करेंगे। उन्होंने कहा कि मानसून से पहले के तीन महीनों के भीतर विकासात्मक परियोजनाओं को पूरा करना महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, नागरिकों और ठेकेदारों से विकास को गति देने में सरकार का सहयोग करने का आहवान किया जिनमें प्रदेश के विशेष रूप से कुल्लू, सिरमौर, चंबा, लाहौल-स्पीति और किन्नौर जिलों के दुर्गम क्षेत्र शामिल हैं।

वन निगम ने रायल्टी राजस्व से अर्जित 41.30 करोड़ रुपये का चेक मुख्यमंत्री को भेंट किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मूल्य निर्धारण समिति की बैठक हुई, जिसमें गैर लकड़ी वन उपज की नई दरों और रायल्टी को मंजूरी प्रदान की गई। इस समिति की पिछली बैठक वर्ष 2022 में आयोजित की गई थी। बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य वन विकास निगम को निजी ठेकेदारों को काम पर रखने की वर्तमान प्रथा को समाप्त कर, स्वयं साइडर वुड स्टंप निकालने का कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने लगभग 10,000 साइडर वुड स्टंप निकालने के लिए रोडमैप तैयार करने के भी निर्देश दिए।

इस अवसर पर निगम ने खैर और साल वृक्षों की सिल्वीकल्चर कटाई से राजस्व के रूप में प्राप्त रॉयल्टी का 41.30 करोड़ रुपये का चेक मुख्यमंत्री को भेंट किया। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति से की गई यह कटाई न केवल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए लाभकारी रही है, बल्कि राज्य के राजस्व में भी योगदान दे रही है।

मुख्यमंत्री ने वन विभाग को गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए जंगलों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए त्वरित और प्रभावी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वन अग्निशमन सेवाओं को तुरंत कारवाई करनी चाहिए और स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाकर आग की घटनाओं को नियंत्रित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने पौधों की जीवित रहने की दर में सुधार पर भी बल दिया।

मुख्यमंत्री ने क्षतिग्रस्त वृक्षों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि नुकसान को कम कर राज्य के राजस्व में वृद्धि किया जा सके।

राज्य वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची अतिरिक्त मुख्य सचिव वन के.के.पंत, प्रधान मुख्य अरण्यपाल समीर रस्तोगी, राज्य वन विकास निगम के प्रबंध निदेशक संजय सूद और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

टेरर और टॉक साथ नहीं चल सकते:जयराम

शिमला/शैल। सिटीजन फॉर नेशनल सिक्योरिटी द्वारा सीटीओ से शेर रे पंजाब और रीज तक तिरंगा यात्रा का

आयोजन किया गया। यात्रा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस यात्रा में व्यापार मंडल, रोटरी क्लब, सिंह सभा और बड़ी संख्या में सामाजिक संस्थाओं ने भाग लिया।

इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आज का भारत बदल चुका है। यह नया भारत शांति चाहता है, पर आतंक के समूल विनाश के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तत्पर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने स्पष्ट कर दिया है कि अब भारत किसी प्रकार के नुक्लियर धमकी को बर्दाश्त नहीं करेगा।

उन्होंने कहा कि टेरर और टॉक साथ नहीं चल सकते। टेरर और ट्रेड का पाखंड अब नहीं चलेगा। जब-जब खून बहेगा, पानी का रास्ता बंद होगा। ऑपरेशन सिन्दूर स्थगित है, पर समाप्त नहीं। पाकिस्तान से बात होगी तो अब सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर ही होगी या आतंक के समूल नाश पर।

उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिन्दूर केवल सैन्य कारवाई नहीं, बल्कि यह न्याय और राष्ट्र सम्मान की अखंड प्रतिज्ञा है। जिसे भारत ने पूरे विश्व के सामने साकार किया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर जैश, लश्कर और हिज़बुल जैसे वैश्विक आतंक के अड्डों को ध्वस्त किया है।

डॉ बिंदल ने इस अवसर पर कहा दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। बिंदल ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वह घिनौना सच देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े-बड़े अफसर उमड़ पड़े। यह प्रायोजित आतंकवाद का बहुत बड़ा सबूत है। केंद्र की मोदी सरकार भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाती रहेगी।

बालिका, महिला सशक्तिकरण और प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल सरकार की अभिनव पहल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में लैंगिक समानता और बाल्यकाल के समावेशी विकास की दिशा में वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा अनेक नवोन्मेषी कदम उठाए गए हैं। सरकार के इन प्रयासों के फलस्वरूप बाल लिंगानुपात में वृद्धि देखी गई है। सरकार के सत्त प्रयासों के फलस्वरूप गत दो वर्षों में बाल लिंगानुपात 947 से बढ़कर 964 पहुंच गया है।

बालिकाओं, महिलाओं और प्रारंभिक शिक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश में अनेक अभिनव कदम उठाए जा रहे हैं। आर्थिक परिस्थितियों के कारण वंचित परिवारों के लिए प्रदेश सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। इन्हीं में से एक योजना है 'इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना'। इस योजना का उद्देश्य बीपीएल परिवारों में जन्म लेने वाली लड़कियों का भविष्य उज्ज्वल करना है। योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा बीपीएल परिवार में जन्म लेने वाली प्रत्येक लड़की के जन्म के समय 25,000 रुपये की राशि बीमा कंपनी के पास जमा किए करवाई जाएगी। इस योजना में माता-पिता दोनों के लिए 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवरेज भी शामिल है।

योजना के तहत बीमा की मैच्योरिटी पर यह राशि बालिका को 18 वर्ष की आयु से 27 वर्ष की आयु तक उसकी इच्छानुसार प्रदान की जाएगी। सरकार की यह नई पहल बालिकाओं के कल्याण के लिए चलाई जा रही अन्य योजनाओं जैसे बेटी है अनमोल इत्यादि को संबल प्रदान करेगी।

कामकाजी महिलाओं की मदद के लिए सरकार द्वारा सोलन, नेरी, दारूही, पालमपुर, लुथान, बद्दी, गगरेट, नगरोटा बगवां, चनौर औद्योगिक क्षेत्र और सोलन में मेडिकल डिवाइसिज पार्क सहित 13 नए कामकाजी महिला छात्रवासों का निर्माण किया जाएगा। 132 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले ये छात्रावास महिलाओं के लिए सुरक्षित और किफायती आवास की जरूरत को पूरा करने में सहायक साबित होंगे।

शिक्षा के क्षेत्र में नौनिहालों को बेहतर प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं। इस दिशा में राज्य में सभी 18,925 आंगनवाड़ी केंद्रों को 'आंगनवाड़ी सह प्री-स्कूलों' में बदला जाएगा। ये केंद्र 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को खेलकूद आधारित प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इस आधारभूत शिक्षा को प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे बच्चों को एक मजबूत शैक्षणिक शुरुआत मिलेगी।

प्रदेश सरकार की यह दूरदर्शी उपाय समावेशी, समग्र विकास और सामाजिक कल्याण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित कर रहे हैं। बालिकाओं, महिलाओं और बच्चों पर केंद्रित योजनाओं से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को साकार कर रहे हैं।

कुलदीप कुमार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष से एससीडीपी बजट में कटौती पर चर्चा की

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार ने नई दिल्ली

में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना से भेंट की। इस मौके पर आयोग के सदस्य अधिवक्ता विजय डोगरा और दिग्विजय मल्होत्रा भी उपस्थित रहे।

कुलदीप कुमार ने राज्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों, विशेषकर अनुसूचित जाति विकास योजना एससीडीपी के अंतर्गत बजट में कटौती के संबंध में चर्चा की। उन्होंने राज्य के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रभाग के अंतर्गत बजट प्रावधान करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने छावनी क्षेत्रों के निकट या मध्य में रहने वाली आबादी के मुद्दों को हल करने के लिए आयोग से हस्तक्षेप करने और इन्हें रक्षा मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत करने का भी आग्रह किया।

उन्होंने आयोग की गतिविधियों के बारे में भी अध्यक्ष को अवगत करवाया और कर्त्तव्यों के निर्वहन के दौरान आयोग को सुरक्षा प्रदान करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने आयोग से राज्य समीक्षा बैठक की तिथि निर्धारित करने का भी आग्रह किया।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने उनके मुद्दों को ध्यानपूर्वक सुना और राज्य को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

वाणिज्य मंत्री से तुर्की से सेब आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग

शिमला/शैल। हिमालयन एप्पल ग्रोअर्स सोसायटी के बैनर तले

सेब उत्पादकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से उनके कार्यालय में भेंट की।

प्रतिनिधिमंडल ने तुर्की से तेजी से बढ़ते सेब आयात को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की और इस पर तत्काल पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को ज्ञापन सौंपा और बताया कि इस सस्ते और सब्सिडी वाले आयात के कारण देश के बागवानों को भारी घाटा हो रहा है और लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रहा।

प्रतिनिधिमंडल ने यह भी उजागर किया कि तुर्की एक ऐसा देश है जो भारत में आतंकवाद फैलाने वाले देश पाकिस्तान को सैन्य सहायता और रक्षा उपकरण प्रदान करता है।

ऐसे देश से आयात न केवल देश की आर्थिकी के लिए नुकसानदायक है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत चिंताजनक है।

प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि सेब केवल एक फसल नहीं, बल्कि पहाड़ी राज्यों की अर्थव्यवस्था और लाखों किसानों की आजीविका का आधार है।

प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष प्रमुख मांगें रखीं:

1. तुर्की से सेब के आयात पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाये।

2. अन्य देशों से सेब आयात पर न्यूनतम आयात मूल्य (MIP) की सीमा को बढ़ाया जाये।

3. आयातित सेबों पर गुणवत्ता और पादप स्वच्छता (phytosanitary) मानकों को सख्ती से लागू किया जाये, ताकि किसी प्रकार के रोग एवं विषाणु सेब के माध्यम से हमारे देश में प्रवेश न कर पाये।

केन्द्रीय मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया।

महर्षि वाल्मीकि सम्पूर्ण स्वच्छता पुरस्कार के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी

शिमला/शैल। हिमाचल सरकार ने महर्षि वाल्मीकि सम्पूर्ण स्वच्छता पुरस्कार के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस पहल का उद्देश्य ओडीएफ प्लस म डल गांवों में व्यापक स्वच्छता और सफाई हासिल करने के लिए ग्राम पंचायतों को मान्यता देना और पुरस्कृत करना है। इसमें प्रभावी ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन और समग्र स्वच्छता बनाए रखना शामिल है।

विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि स्वच्छ हिमाचल के लक्ष्य को प्राप्त करने प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए दिशा-निर्देशों को संशोधित किया गया है। उन्होंने बताया कि पुरस्कार के लिए पात्रता मानदण्डों में प्रभावी स्वच्छता कार्य, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, कुशल अपशिष्ट प्रबंधन, सामुदायिक भागीदारी और अभिनव प्रयास शामिल किए गए हैं। उन्होंने बताया कि चयन प्रक्रिया एक स्कोरिंग पैटर्न पर आधारित होगी जो विभिन्न स्वच्छता मापदण्डों को महत्व देती है। इसमें ओडीएफ स्थिति को बनाए रखने और ओडीएफ प्लस म डल गांव का दर्जा हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

विजेता ग्राम पंचायतों के लिए प्रोत्साहन राशि की घोषणा की गई है। खण्ड स्तर पर प्रत्येक खण्ड में एक पंचायत के लिए एक लाख रुपये, जिला स्तर पर यदि किसी जिला में 300 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं तो दो ग्राम पंचायतें तीन-तीन लाख रुपये का पुरस्कार प्राप्त कर सकती हैं, सम्भाग स्तर पर प्रत्येक सम्भाग स्तर में एक पंचायत के लिए 5 लाख रुपये और राज्य स्तर पर एक पंचायत के लिए 10 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे।

प्रवक्ता ने बताया कि सम्पूर्ण और निष्पक्ष मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक, जिला, संभाग और राज्य स्तर पर मूल्यांकन समितियां स्थापित की जाएंगी। खण्ड स्तर पर आवेदन 30 जून, 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे और विजेताओं की घोषणा 20 अगस्त, 2025 को की जाएगी। जिला स्तर के पुरस्कारों की घोषणा 14 सितम्बर, उप-मण्डल स्तर के विजेताओं की घोषणाा 10 अक्तूबर और राज्य स्तरीय पुरस्कार की विजेता पंचायत की घोषणा 30 अक्तूबर को की जाएगी।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

बैंस ने प्रदेश सरकार से किया सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह

- एस.आई.टी की कार्यप्रणाली पर उठाये गंभीर सवाल
- बैंस द्वारा दर्ज करवायी गयी शिकायत की जांच क्यों नहीं?
- बैंस की शिकायत में दर्ज हैं कई बड़े नाम

शिमला/शैल। क्या युद्ध चन्द बैंस को हिमाचल सरकार सुरक्षा उपलब्ध करवायेगी? क्या युद्ध चन्द बैंस की शिकायत में नामितों को विजिलैन्स की एस. आई.टी. जांच के लिये बुलायेगी? यह प्रश्न बैंस द्वारा 19 मई को डी.जी.पी. के नाम भेजी शिकायत एवं आग्रह के बाद चर्चा में आ गये हैं। बैंस ने इस पत्र की प्रत्तियां प्रदेश के राज्यपाल, मुख्य सचिव और गृह सचिव तथा एस. पी. विजिलैन्स को भी भेजी है। बैंस ने इस पत्र में खुलासा किया है कि उसने सितम्बर 2024 में व्यास नदी के किनारे हो रहे अवैध खनन और कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक धर्मशाला में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर नई दिल्ली स्थित ई.डी. कार्यालय में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। इस शिकायत पर हुई प्रारंभिक जांच के बाद अवैध खनन प्रकरण में ज्ञान चन्द और संजय धीमान ई.डी. की हिरासत में चल रहे हैं। बैंस की ई.डी. में इस शिकायत के बाद प्रदेश विजिलैन्स ने उसके खिलाफ 8 जनवरी 2025 को ऊना में उसके ऋण प्रकरण पर एक आपराधिक मामला दर्ज कर लिया। यह आपराधिक मामला दर्ज होने के बाद बैंस ने प्रदेश उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत की गुहार लगा दी। इस पर उच्च न्यायालय ने बैंस को जांच में शामिल होने की शर्त पर अस्थायी जमानत दे दी। जमानत की शर्तो की अनुपालन में बैंस नियमित रूप से जांच में शामिल होता रहा। विजिलैन्स की हर जांच के बाद उसकी स्टेटस रिपोर्ट भी उच्च न्यायालय को सौंपी जाती रही। इसी जांच के दौरान बैंस ने कांगड़ा सहकारी बैंक को लेकर एक विधिवत शिकायत विजिलैन्स में दायर कर दी। उच्च न्यायालय ने विजिलैन्स द्वारा समय-समय पर सौंपी गयी स्टेटस रिपोर्टो के आधार पर बैंस को नियमित जमानत दे दी।

बैंस विजिलैन्स द्वारा बुलाये जाने पर हर बार जांच में शामिल होता रहा है। लेकिन बैंस के मुताबिक विजिलैन्स ने उसकी शिकायत में नामितों से एक बार भी पूछताछ नहीं की है। जबकि उसने बैंक अधिकारियों और अन्य के खिलाफ गंभीर आरोप लगाये हैं। यह सामान्य समझ की बात है कि एक अपराधी को भी दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने का पूरा अधिकार है। उसकी शिकायत को बिना जांच के खत्म नहीं किया जा सकता। बैंस ने जिन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा रखी है वह सरकार में बड़े नाम हैं और बैंस का दावा है कि उसके पास इन लोगों के खिलाफ पर्याप्त दस्तावेजी प्रमाण है। बैंस के इस दावे और एस.आई.टी. द्वारा अब तक की गयी एक पक्षीय जांच और एस.आई.टी की कार्य प्रणाली पर इस पत्र में उठाये गये सवाल अपने में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यह स्पष्ट है की बैंस के खिलाफ चल रही जांच में तब तक अदालत में चालान नहीं सौंपा जा सकता जब तक एस.आई.टी. बैंस की शिकायत पर भी उसी प्रक्रिया में जांच नहीं कर लेती है। ऐसे में बैंस ने जो प्रदेश सरकार से सुरक्षा मांग रखी है उस आग्रह को ठुकराना इन परिस्थितियों में आसान नहीं होगा।

यह है बैंस का डीजीपी के नामपत्र

To
Director General of Police,
Himachal Police Headquarters ,Nigam Vihar
Shimla ,Himachal Pradesh (171002)
Subject – Request for Security Cover Within Himachal Pradesh
Sir,

I Yudh Chand Bains ,a resident of District Mandi had made a complaint against the Illegal mining within beas basin and Corruption within Kangra Central Cooperative Bank, Dharmshala in September 2024 with Enforcement Directorate Office ,New Delhi. The Complaint involved Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu ,his close associate Gyan Chand (already arrested), Sanjay Dhiman (already arrested), Political adviser to CM Sunil Bittu,Principal Secreatry to CM Vivek Bhatia,Doon MLA Ram Kumar Chaudhary, Secretary Cooperative C Paulrasu ,Kangra Central Cooperative Bank Chairman Kuldeep Pathania, Vicky Handa(Jeweller Close to Kuldeep Pathania and Sunil Bittu).

Since the submission of my Complaint with the ED Office ,I have been pressurized through different channels, with both lucrative offers as well as threat,, to withdraw my complaint. When every attempt to coerce me into withdrawing my complaint failed ,a fabricated and politically motivated FIR was filed against me on 8.01.2025 at SV & ACB, Police Station Una.

Using this FIR as a revenge tool, I have been summoned regularly for attending Inquiry at Vigilance Headquarters ,Shimla. Since January,2025 i have been constantly harassed on the pretext of Inquiry and it has been more than 4 months now that I am still being summoned again and again despite the fact that all the questions raised by Inquiry Officer had been answered multiple times , all the record along with documents at my disposal have been already either seized by SIT or has been handed over by myself Voluntarily.

Sir, the conduct of Members of SIT seems questionable and motivated by ulterior designs for following reasons

• Summons to call me are being used to track my locations and whereabouts with the motive of leaking my confidential information to miscreants ,causing a threat to my personal security. To Justify this Claim, in the starting weeks of this planned inquiry ,I was being called at 10:30AM and Inquiry Officers allowed me to leave only after 6:00PM. I have Security from Ministry of Home Affairs and sensing this design of allowing me to leave inquiry only after it was dark outside, my PSO's got alert. On one such evening ,PSO's accompanying warned me of a suspicious vehicle following us as soon as we left Vigilance HQ. Apprising the danger to my Safety, the PSO's stopped the vehicle and confronted the people siting inside. To my Surprise ,all occupants were staffed at Police HQ and even the vehicle was registered with Police HQ with registration number HP 03 C 7354. What was the need of following my vehicle, on whose direction was i being followed and to whom my locations were being shared ?

• I have submitted a Formal written Complaint with the SIT at Vigilance Office, Shimla highlighting how money was extorted from me on the pretext of OTS in Kangra Central Cooperative Bank and saving my properties along with the names of those involved in this corrupt extortion racket from CM Office To

Chairman of Kangra Central Cooperative Bank (as have been named in Complaint to ED). Since January,2025, I have attended the said inquiry more than 30 times ,but not once those named in my formal complaint have been summoned ,why ? Is this a one way inquiry, sole motive of which is to somehow fabricate me in a false case and coerce me into withdrawing my complaint ?

Sir, I have a potential threat to my life, for mycomplaint against the powerful and influential and this act of constantly summoning me ,making me to wait for whole day in waiting room, seems suspicious and part of a bigger conspiracy to track my movement and somehow cause harm to me through miscreants. Supporters of these powerful and influential named in my complaint can take the form of a Mob at public places to harm me. This threat to my life is the only reason which has forced me to relocate myself out of Himachal Pradesh. If anything happens either to me or my family, then those named in my complaint shall be held responsible.

I thus request your good office to please take note of this grave issue and provide me with ample security cover whenever I am summoned to attend the inquiry ,from the time I enter the boundary of Himachal Pradesh and till I leave the state boundary. I have been Summoned to attend inquiry on 20th May, 2025 at Shimla Vigilance Office at 10:30 AM. My fight is scheduled to land at Shimla airport at 7:30AM on 20th May, 2025.

I Further request your good office to please direct SP ,SV &ACB ,Shimla and members of SIT to act on my formal written complaint submitted with them and involve and Include all those named in my complaint within the ambit of this inquiry.

"Justice must not only be done, but must also be seen to be done"

Regards
Yudh Chand Bains
R/O Village Bhiura,P.O. Rajgarh,Tehsil Balh, Distt.
Mandi ,Himachal Pradesh (175027)
Contact – 9041049507
Dated-19th May, 2025

• Copy to Hon'ble Governor, Himachal Pradesh
• Copy to Chief Secreatry ,Govt. Of Himachal Pradesh
• Copy to Secreatry Home ,Govt. Of Himachal Pradesh
• Copy to SP, SV & ACB,Shimla